शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-40 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 2-9 अक्तूबर 2023 मूल्य पांच रूपए

सुक्खु सरकार का पत्रकारों को तोहफा पांच गुणा बढ़ाये मकानों के किराये

- क्या 65 वर्ष से अधिक के नहीं कर सकते पत्रकारिता
- क्या यह कांग्रेस की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है
- क्या विज्ञापनों में भेदभाव कर सकती है सरकार

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने 16 अगस्त को लिये एक फैसले के पत्रकारों के लिए सरकारी आवास आबंटन नियमों में संशोधन करके उनके किराए में पांच गुणा वृद्धि कर दी है। इसी के साथ प्रस्थापित पत्रकारों की शैक्षणिक योग्यता और आयु प्रमाण पत्र भी मांग लिये हैं। चर्चा है कि 65 वर्ष से अधिक की आयु वालों से आवास खाली करवा लिये जायेंगे। वैसे जब पत्रकारों को आवास आबंटित होते हैं तब उन्हें ऐसी आयु सीमा की कोई बंदिश नहीं बतायी जाती। क्योंकि पत्रकार कोई सरकारी कर्मचारी तो होता नहीं है। वैसे पत्रकारों को सरकार कोई सुविधा प्रदान करेगी ही ऐसा भी कोई नियम नहीं है। पत्रकार और पत्रकारिता की लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या अहमियत होती है इसका अन्दाजा इसी से लग जाता है की पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा पिल्लर की संज्ञा हासिल है। सरकार की नीतियों की प्रासंगिकता और व्यवहारिकता पर तीखे सवाल पूछना यह पत्रकार का धर्म और कर्म माना जाता है। समाज के हर उत्पीड़ित की आवाज सार्वजनिक रूप से सरकार के सामने रखना पत्रकार से ही अपेक्षित रहता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बेबाकी से आवाज उठाना पत्रकार से ही उम्मीद की जाती है। इसीलिये किसी समय यह कहा गया था की **"गर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो"** पत्रकार सरकार का प्रचारक नहीं होता है। परन्तु आज की सरकारों को तो शायद गोदी मीडिया पसन्द है और उनकी आवश्यकता है। इसलिये सुक्खु को सरकार ने भी मीडिया को गोदी बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है। यह अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गोदी मीडिया कर्मियों को चिन्हित करके उनके बहिष्कार का फैसला लिया है। परन्तु सुक्खु तो व्यवस्था बदलने चले हैं और इसकी शुरुआत पत्रकारों से ही की जा रही है ताकि सरकार में फैली अराजकता और भ्रष्टाचार को दिये जा रहे हैं संरक्षण पर कोई आवाज न उठ सके। इसलिये सुक्खु सरकार का कोई मंत्री या कांग्रेस संगठन का कोई भी पदाधिकारी इस पर कुछ नहीं बोल रहा है।

16 अगस्त को जो नीति संशोधन किया गया है उसमें साप्ताहिक समाचार पत्रों का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। क्योंकि इस सरकार ने सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्रों के विज्ञापन ही बन्द कर दिये। इस सरकार के सलाहकारों और निति नियन्ताओं को यह नहीं पता की साप्ताहिक समाचार पत्रों के लिये भारत सरकार ने अलग से नीति बना रखी है। प्रचार प्रसार के लिये साप्ताहिक पत्रों की वेबसाइट बनाने की सुविधा दे रखी है। साप्ताहिक पत्रों का भी डीएवीपी विज्ञापनों के लिये पंजीकरण और दर निर्धारण करता है। क्योंकि साप्ताहिक पत्रों का विषय विश्लेषण रहता है न की सूचना देना। यह साप्ताहिक पत्र ही थे जिन्होंने पिछली सरकारों का विश्लेषण करते हुये उनकी हार की गणना की थी। लेकिन सुक्खु सरकार साप्ताहिक समाचार पत्रों का गला घोटकर उनको बन्द करवाना चाहती है।

पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति अंतिम क्षण तक सक्रिय रहता है क्योंकि उसके अनुभव और लेखन में तथ्य परक वृद्धि होती रहती है। लेकिन सुक्खु सरकार मीडिया को गोदी बनाने के लिये उससे सुविधायें छीनने पर आ गयी है। जबकि विज्ञापनों को लेकर प्रेस परिषद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्योंकि विज्ञापनों पर होने वाला खर्च किसी राजनीतिक दल या नेता का व्यक्तिगत पैसा नहीं होता है। उसके आबंटन और खर्च में पारदर्शिता रहना आवश्यक है। लेकिन सुक्खु सरकार तीखे सवाल पूछने वालों का गला घोंटना चाहती है। जबकि यही सरकार अपना साप्ताहिक पत्र प्रकाशित कर रही है। गोदी में बैठने की भूमिका निभाने वालों को एक-एक अंक में लाखों के विज्ञापन दे रही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार तीखे सवाल पूछने वालों को सबक सिखाने की नीयत से यह संशोधन लेकर आयी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इसे बैक डेट से लागू किया जा सकता है? क्या पत्रकार सरकार के नौकर है या अपने संस्थान के। क्या संस्थाओं को सरकार इस तरह से नियंत्रित कर सकती है। जो प्रश्न पत्रकारों से जानकारी के नाम पर पूछे जा रहे हैं क्या वह उनके संस्थाओं से नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या सरकार संस्थान के बिना किसी पत्रकार को मान्यता देती है? क्या कोई भी नियम 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को सक्रिय पत्रकारिता से रोक सकता है? जब संस्थान के बिना पत्रकार को मानता नहीं दी जा सकती तब क्या हक संस्थान का नहीं होना चाहिए कि वह अपने किस व्यक्ति को सरकारी सुविधा देना चाहता है? सुक्खु सरकार ने जिस तरह से पत्रकारों का गला दबाने की चाल चली है क्या वह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नीति है यह सवाल भी आने वाले समय में पूछा जायेगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(अनुभाग डी)

संख्याः जी०ए०डी०-डी०(ए)1-1/2022 तारीख शिमला-02 16 अगस्त, 2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, फण्डामैंटल रूल्ज के रूल 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः जी०ए०डी०-(डी)-7(जी)1-12/81, तारीख 1 जून, 1994 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 18 जुलाई, 1994 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन(सामान्य पूल) तेरहवां संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नियम 8 का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम,1994 के नियम 8 के आधार संख्या (9) में :-

(i) खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों में जिनकी न्यूनतम प्रसार संख्या 60,000 प्रतियाँ हो जिनमें से 10,000 प्रतियाँ हिमाचल प्रदेश मे प्रसारित होती हों के नियमित संवाद्दाता और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाली समाचार एजेन्सी या इलैक्ट्रोनिक समाचार चैनल के संवाद्दाता, शिमला में टाइप -IV तक के सरकारी आवास के आवंटन के लिए पात्र होंगे, :

परंतु वह/उसके पास :-

(क) पत्रकारिता/जनसंचार में स्नातक की उपाधि/डिपलोमा धारित करता/करती हो;

(ख) इस क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो ;

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया राज्य स्तरीय प्रत्यायन हो ;

(घ) शिमला में उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई आवास न हो।

परिचालन/व्यूअरशिप (समीक्षक) के सम्बन्ध में निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश का प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाएगा।";

(ii) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि खण्ड (i) के अन्तर्गत आवास का आबंटिती, उसे आवंटित आवास के प्रकार की लाइसेंस फीस का निम्नानुसार संदाय करेगा :-

टाइप-III - ₹ 2500 प्रति मास।

टाइप-IV - ₹ 5000 प्रति माह।" और

(iii) खण्ड (iv) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीख शिमला-2 16 अगस्त, 2023

मुख्यमंत्री ने निगम को आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और राशन उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक

आपूर्ति निगम सीमित के निदेशक मंडल की 173वीं बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की गई है और पात्र लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि प्रभावित परिवार अपने उचित अधिकारों से वंचित न रहें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हाट प्लेट, सुरक्षा पाइप सहित एलपीजी घरेलू रिफिल और ब्लू बुक की लागत सहित सभी संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवा रही है जिसके अंतर्गत राशन पैकेज में 20 किलो गेहूं का आटा, 15 किलो चावल, 3 किलो दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर सोया रिफाइंड तेल, 1 किलो डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलो चीनी शामिल है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क राशन की यह सुविधा 31 मार्च, 2024 तक प्रदान की जाएगी। इससे प्रभावितों को मूलभूत खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1955 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया है और 87 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निगम को पूरी तरह से डिजिटल, वाणिज्यिक और पेशेवर इकाई बनाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफएमसीजी उत्पादों की खरीद के लिए निगम को गोदरेज और बजाज जैसी अग्रणी कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकें।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निगम से मरीजों की सुविधा के लिए और उन्हें उचित दरों पर दवाएं और अन्य सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 52 नई उचित मूल्य दवाओं की दुकानें खोलने के लिए भी कहा ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।

निगम के गैर सरकारी निदेशक, प्रधान सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आर.डी. नजीम, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, प्रबंध निदेशक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम राजेश्वर गोयल, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार संदीप कदम, राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यकारी निदेशक सचिन कंवल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

विशेष रूप से सक्षम मुस्कान और प्रतिभा ठाकुर ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। प्रदेश में कॉलेज काडर में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्त दिव्यांग मुस्कान और प्रतिभा ठाकुर ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। विशेष रूप से सक्षम मुस्कान और प्रतिभा ठाकुर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में संगीत और राजनीति विज्ञान की अध्येता हैं।

राज्यपाल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने उन्हें हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की यह होनहार बेटियां सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जीवन में अनेक संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की और सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुईं। राज्यपाल ने इस अवसर पर उपस्थित प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव की विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना की।

मुस्कान के पिता जय चन्द भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी कृति चंदेल को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले की युवा उद्यमी कृति चंदेल को हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन क्षेत्र मे 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है कि लड़कियां सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। उनकी इस उपलब्धि से अन्य लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने और प्रदेश का नाम रोशन करने की प्रेरणा मिलेगी।

दिव्यांगजनों के लिए तीन छात्रवृत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया 1 अक्तूबर से शुरू

शिमला/शैल। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से तीन छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा नौवीं तथा दसवीं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा उच्च श्रेणी स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

इन छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण प्रथम अक्तूबर, 2023 से आरंभ हो गया है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं की विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.depwd.gov.in अथवा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिये पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2023 तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 31 दिसंबर, 2023 निर्धारित की गई है।

उद्योग मंत्री ने जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लिया

शिमला/शैल। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 52वीं बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश का प्रतिनिधित्व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया।

बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए जिसके परिणामस्वरूप व्यवसायों के अनुपालन बोझ को कम किया जाएगा। जीएसटी परिषद ने शराब के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया। शराब के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले ईएनए पर वर्तमान में 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

उद्योग मंत्री ने चर्चा में भाग लेते हुए मांग की कि जीएसटी परिषद को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ईएनए पर जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईएनए पर जीएसटी से छूट देने से राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना अनुपालन सरल हो जाएगा, क्योंकि ईएनए एक मध्यवर्ती उत्पाद है। परिषद ने हिमाचल प्रदेश के तर्कों की सराहना की।

हिमाचल प्रदेश के दल ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के संबंध में अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने के लिए विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ संवाद किया। उद्योग मंत्री ने अन्य राज्य के मंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार जीएसटी के पारदर्शी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रही है तथा करदाताओं के अनुपालन को आसान बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधान सचिव भरत खेड़ा, आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी डॉ. यूनुस और अतिरिक्त आयुक्त राकेश शर्मा भी इस अवसर पर थे।

आईपीएस अधिकारी गौरव सिंह हिमाचल रक्षक अवार्ड से सम्मानित

शिमला/शैल। 19 वें हिमाचल उत्सव में सोलन के एसपी और आईपीएस अधिकारी गौरव सिंह को हिमाचल रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। गौरव सिंह और उनकी

पुलिस कर्मियों की टीम को ये अवार्ड राज्य के पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रदान किया किया। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन महीनों के दौरान गौरव सिंह के सोलन पुलिस कप्तान का कार्यभार संभालने के बाद चिट्टा और नशा माफिया पर नकेल कसते हुए 32 केस दर्ज किए गए और बाहरी राज्यों के 32 सप्लायर को गिरफ्तार कर सप्लाई चेन को पूरी तरह काट दिया। अब तक केवल छोटी मछलियों को पकड़े जाने की खबरें आती थीं लेकिन गौरव सिंह ने नशे को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी रणनीति में बडे सप्लायरों को पकड़ कर नशे की सप्लाई ही खत्म करने का काम किया। गौरव सिंह के नेतृत्व में अब तक सोलन पुलिस ने 6 बड़े ड्रग नेटवर्क पूरी तरह खत्म कर दिए हैं। इस दौरान केवल 3 महीनों में ही इस टीम ने 400 ग्राम से ज्यादा चिट्टा, 5 किलो से ज्यादा अफीम, 3 किलो से ज्यादा चरस, 11 किलों पापी हस्क और मेथ भी जब्त की। हिमाचल उत्सव के मंच पर जब एसी गौरव सिंह और उनकी टीम को सम्मानित किया गया।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग का अवैध शराब एवं कर चोरी के विरूद्ध अभियान जारी

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. युनुस ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर प्रवर्तन दल ऊना ने एक रजत आभूषण व्यापारी के घर से 4,64,42,227 रुपये के आभूषण पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। यह आभूषण बिना बिल अथवा दस्तावेजों के थे। इस मामले में विभाग द्वारा जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 15,32,594 रुपये का अर्थदण्ड वसूला गया है।

उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में विभाग की देहरा स्थित टीम ने भी रात्रि चैकिंग के दौरान बिना बिल के सामान पर जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 1,00,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया है।

इसके अतिरिक्त आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न टीमों ने कार्यवाही करते हुए लगभग 250 बल्क लीटर शराब जब्त कर नष्ट की है। इस कार्यवाही के दौरान बीबीएन (राजस्व जिला) की टीम ने बरोटीवाला, कालू झंडा, कुल्हारीवाला और कुंझल क्षेत्र में छापेमारी की तथा 115 बल्क लीटर शराब घर व करियाना की दुकान से जब्त की। यह शराब चण्डीगढ़ में बिक्री के लिए थी।

उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर की आबकारी टीम ने गांव जामनी घाट के निकट बोतलों एवं कैनों में भरी लगभग 90 लीटर अवैध शराब पकड़ी जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

इसी तरह टीम शिमला ने संदिग्ध करियाना की दुकानों तथा ढाबों पर छापेमारी की तथा आबकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत मामला दर्ज करते हुए 22 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की।

आयुक्त ने अवगत करवाया कि विभाग द्वारा पिछले कुछ समय में 77000 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त कर नष्ट करने के साथ ही लगभग 230 मामले आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए हैं। इस कार्य को अंजाम देने में विभाग की 26 टीमें दिन-रात कार्यरत हैं।

आबकारी आयुक्त ने कहा कि इसके लिए चौबीसों घंटे सक्रिय एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि अवैध शराब तथा कर चोरी के मामले संज्ञान में आते ही टॉल-फ्री नम्बर 1800-180-8060 तथा व्हट्सऐप नम्बर 94183-31426 पर शिकायत दर्ज करें ताकि इस अभियान को और तेज करके अवैध शराब के कारोबार तथा कर चोरी पर पूर्णतः विराम लगाया जा सके।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने किया पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भूकम्प और भू-स्खलन जैसे भौगोलिक खतरों से उत्पन्न चुनौतियां विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारम्भ

आपदा से बचाव के लिए नियमों और मानवीय स्वभाव में बदलाव की जताई आवश्यकता
प्रदेश में अत्याधिक बादल फटने की घटनाओं के व्यापक अध्ययन का आग्रह किया
आपदा में सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाएगी प्रदेश सरकारः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में कड़ा कानून बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में गृह निर्माण के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की अनुमति, भूमि के भार वहन करने की क्षमता का पता लगाने के साथ-साथ जल निकासी की समुचित व्यवस्था पर कानून बनाया जाएगा। उन्होंने इसमें लोगों से राज्य सरकार को सहयोग का आहवान भी किया। उन्होंने कहा कि आज आपदा से अमूल्य जीवन एवं सम्पत्ति के नुकसान को कम करने के लिए नियमों तथा मानवीय स्वभाव में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन बनाकर ही आपदा की संभावना तथा इससे होने वाले नुकसान को न्यून किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भूकम्प और भू-स्खलन जैसे भौगोलिक खतरों से उत्पन्न चुनौतियां, विषय पर राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के तत्वावधान में दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में इस बार बरसात में भारी बारिश, बादल फटने और बांधों से अत्याधिक पानी छोड़े जाने के कारण बहुत अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह से ही राज्य में बारिश हो रही थी और मानसून में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण मानव जीवन और संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इस आपदा के लिए मानवीय लालसा व असंवेदनशीलता इत्यादि भी कारण रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत नालों इत्यादि से समुचित दूरी पर घर बनाने और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें चूक से आपदा में जान-माल के नुकसान की आशंका और भी बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही की बरसात में राज्य में बादल फटने की बहुत घटनाएं हुई हैं, जिनका व्यापक अध्ययन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी दृष्टिगोचर हो रहा है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इस बार काफी ज्यादा बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से राज्य सरकार ने आपदा के दौरान बेहतर काम किया और रिकॉर्ड 48 घंटों के भीतर प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और टेलीफोन सहित अन्य आवश्यक सेवाएं अस्थाई रूप से बहाल की गई। राज्य में किसानों-बागवानों को भी असुविधा

न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखते हुए सेब व अन्य नकदी फसलों को समय पर मंडियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में बेहतर प्रयासों के लिए अधिकारियों सहित सभी लोगों की पीठ भी थपथपाई।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बारिश और बाढ़ के अलावा हिमाचल भूकम्प की दृष्टि से भी संवेदनशील है। ऐसे में भूकम्प से बचाव के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिला में दो डॉप्लर रडार स्टेशन स्थापित करने को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे मौसम का सही आकलन करने में मदद मिलेगी और सही समय पर उचित कदम उठाए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने पहाड़ों में सड़क निर्माण के लिए अधिक से अधिक सुरंगें बनाने पर बल दिया ताकि भू-स्खलन के खतरे को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि मटौर-शिमला फोरलेन के निर्माण में सुरंग निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। सोलन-परवाणु फोरलेन पर 90 डिग्री में कटिंग तथा इससे कुछेक स्थानों पर भू-स्खलन की अधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे भू-स्खलन संभावित स्थल चिन्हित किए जाने चाहिए ताकि वहां सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि भविष्य में आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रुपये की एक दीर्घकालीन परियोजना पर भी विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने इस कार्यशाला के आयोजन के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा तथा हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद की सराहना करते हुए कहा कि कार्यशाला के दौरान प्राप्त सुझावों को राज्य सरकार अपनी नीति में उचित अधिमान देगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से आपदा प्रभावितों के लिए कम्बल और राशन के तीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इससे पूर्व प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने कार्यशाला में मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा कहा कि भविष्य की तैयारियों के लिए यह कार्यशाला उपयोगी सिद्ध होगी।

विशेष सचिव राजस्व डी.सी. राणा ने कार्यशाला पर विस्तृत जानकारी दी, जबकि अतिरिक्त सचिव सतपाल धीमान ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, विनोद सुल्तानपुरी, सुदर्शन बबलू, अजय सोलंकी, भुवनेश्वर गौड़, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, सम्बन्धित विभागों के अधिकारी व वैज्ञानिकों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत नियुक्त विशेष शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत नियुक्त विशेष शिक्षकों (एसएमसी/आउटसोर्स) की लम्बित मांग को पूरा करते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है।

उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा प्रारंभिक स्तर पर नियुक्त विशेष शिक्षकों के मानदेय को 8,910 रुपये से बढ़ाकर 14,095 रुपये तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षकों का मानदेय 14,500 रुपये से बढ़ा कर 17,936 रुपये किया गया है। इन विशेष शिक्षकों को यह लाभ प्रथम अक्तूबर, 2023 से प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा के अंतर्गत एसएमसी के अन्तर्गत नियुक्त विशेष शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। इन विशेष शिक्षकों को समान वर्ष में छह दिन का चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एन.एस.एफ.क्यू.) के अन्तर्गत कार्यरत वोकेशनल ट्रेनर्ज का वेतन बढ़ाकर 22 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार विशेष शिक्षकों की मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है तथा उन्हें वेतन वृद्धि प्रदान कर अपना वायदा पूरा किया है।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

एसएमसी शिक्षकों की मांगों के समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश एसएमसी टीचर्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। उनके हितों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया है। यह कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों का उचित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने बजट में एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।

इस अवसर पर एसोसिएशन ने आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को एक लाख 51 हजार 111 रुपये का चेक भेंट किया।

इस अवसर पर विधायक इन्द्र दत्त लखनपाल, विनय कुमार, केवल सिंह पठानिया, मलेन्द्र राजन, एचपी एसएमसी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

ग्राम पंचायत हड़ेटा और कमयाणा हिल टॉप में विकसित होंगी इको-टूरिज़्म गतिविधियां

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को हमीरपुर जिला के नादौन विकास खंड की ग्राम पंचायत हड़ेटा तथा शिमला जिला के मशोबरा विकास खंड में कमयाणा हिल टॉप के लिए स्वीकृत 16.67 करोड़ रुपये की इको-टूरिज़्म परियोजनाओं का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास रंग लाये हैं और इनके पूर्ण होने पर स्थानीय युवाओं को रोज़गार व स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन इको-टूरिज़्म परियोजनाओं के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण और वन्य जीव तथा वनस्पति जीव के संरक्षण के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। सत्त इको-टूरिज़्म, जैव विविधता संरक्षण के लिए क्षेत्र की पर्यटन विकास समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों को भी सक्रिय रूप से इसमें शामिल किया जाएगा। इन परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, वन तथा पर्यटन विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत हड़ेटा में घास के मैदान, रात्रिकालीन शिविर के लिए ट्री-हाउस, पैदल रास्ते तथा प्राकृतिक पथ, कैफेटेरिया, बच्चों के लिए पार्क, सौर ऊर्जा संचालित रोशनी की सुविधा, औषधीय जड़ी-बूटियों की पैदावार सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाएं एवं इससे संबंधित आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत 1.2 हैक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जाएगा और इसमें लगभग 60 स्वयं सहायता समूह शामिल किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि शिमला जिला के कमयाणा हिल टॉप में इस परियोजना के तहत ट्री-टॉप, कैफेटेरिया, प्राकृतिक दृश्यावलियां, बाल-उद्यान, साहसिक गतिविधियां, साइकिलिंग पथ, देवदार जोन, कैक्टस उद्यान तथा तितली उद्यान इत्यादि विकसित किए जाएंगे, ताकि क्षेत्र में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत 24 स्वयं सहायता समूह शामिल किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में पर्यटन क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटकों की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचे के विस्तार तथा इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

धर्मशाला में मैच से 6 घंटे पहले भारी मालवाहक वाहनों के लिए बंद होगी एंट्री

शिमला/शैल। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आयोजित होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के मैचों के लिए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। जिलाधीश कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने एक आदेश जारी कर बताया कि धर्मशाला में होने वाले इन मैचों के दौरान लोगों को आवाजाही में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।

डीसी ने बताया कि मैच से 6 घंटे पहले सीमेंट, सरिया, रेत-बजरी आदि ले जाने वाले बड़े वाहनों की आवाजाही धर्मशाला शहर में बंद कर दी जाएगी। मैच समाप्त होने तक इन बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि रूटीन में चलने वाली इस रूट की बसों और आवश्यक सेवाएं देने वाली गाड़ियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। जिलाधीश कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि ट्रैफिक प्लान की यह व्यवस्था धर्मशाला शहर में 7, 10, 17, 22 और 28 अक्तूबर को होने वाले क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के मैचों के दौरान लागू रहेगी।

उन्होंने बताया कि कांगड़ा, गगल की ओर से धर्मशाला जाने के लिए चौतड़ू-शीला रोड से प्रवेश और धर्मशाला से वाया सकोह निकासी की व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाएं देने वाले वाहनों पर इस दौरान आवाजाही को लेकर ऐसी कोई भी रोक नहीं होगी। उन्होंने शहर के लोगों और मैच देखने आने वाले दर्शकों से भी इस दौरान व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए सहयोग की अपील की है।

रत्न कभी खंडित नहीं होता। अर्थात विद्वान व्यक्ति में कोई साधारण दोष होने पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।

...... आचार्य चाणक्य

सम्पादकीय

शिक्षा पर आयी विश्व बैंक की रिपोर्ट से उठते सवाल

शिक्षा पर विश्व बैंक की इन दिनों रिपोर्ट आयी है। 12 देशों को लेकर आयी इस रिपोर्ट में भारत दूसरे स्थान पर है। जहां दूसरी कक्षा के बच्चे क ख पढ़ने में असमर्थ है। इस सूची में मलावी पहले स्थान पर है। वर्तमान रिपोर्ट से पहले 2018 में भी विश्व बैंक शिक्षा पर रिपोर्ट जारी कर चुका है। इस रिपोर्ट के साथ ही भारत की राष्ट्रीय स्तर की स्वयंसेवी संस्थाओं की भी शिक्षा पर रिपोर्ट आया थी। इस रिपोर्ट में हिमाचल को लेकर भी टिप्पणियां हैं। जिनमें यह कहा गया है कि हमारे सरकारी स्कूलों के चौथी पांचवी के बच्चे दूसरी तीसरी कक्षा की किताब पढ़ने और हिसाब करने में अटकते हैं। आठवीं और नवीं कक्षा के छात्रों की स्थिति तो और भी चिंताजनक बताई गयी है। इन रिपोर्टों पर सरकार की ओर से कोई खंडन नहीं आया है। इन दिनों मोदी सरकार द्वारा लायी गयी नई शिक्षा नीति को लागू करने पर कदम उठाये जा रहे हैं। शिक्षा रोजगारपरक होनी चाहिए यह मांग है। क्योंकि इस समय पढ़े-लिखे बेरोजगारों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। इसलिए शिक्षा रोजगार में सीधा संबंध होना चाहिए। यह समय की मांग बनता जा रहा है। इस परिप्रेक्ष में यह समझना आवश्यक हो जाता है की क्या स्कूली शिक्षा से ही शिक्षा रोजगारपरक हो जानी चाहिए या उसके बाद भी यह प्रश्न आना चाहिए यह एक बड़ा विस्तृत सवाल है। यदि स्कूली शिक्षा के बाद शिक्षा और रोजगार में जुड़ाव होना चाहिए तो इसका अर्थ होगा की स्कूली शिक्षा तक सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए और यह अनिवार्य होनी चाहिए। यह अनिवार्य शिक्षा माध्यमिक स्तर तक या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक होनी चाहिए। यह फैसला एक व्यापक विचार विमर्श के बाद होना चाहिए। अनिवार्य शिक्षा तक निजी क्षेत्र का दखल नहीं होना चाहिए।

इस समय नर्सी केजी से ही निजी से प्राइवेट सेक्टर शिक्षा में बराबर का भागीदार बना हुआ है। हिमाचल जैसे राज्य में भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 45% है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चों की संख्या 55% है। यहीं से शिक्षा में यह विसंगति आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि राजनेताओं से लेकर प्रशासकों और शिक्षकों तक के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इससे सरकारी स्कूलों का प्रबंधन और स्तर प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कमजोर पड़ता जा रहा है। इस समय नई शिक्षा नीति की भूमिका में ही यह कहा गया है की खाड़ी देशों में हेल्परों की बहुत आवश्यकता है और हमारे बच्चों को आसानी से वहां रोजगार मिल जाएगा इसलिए नई शिक्षा नीति में व्यवसायिक प्रशिक्षण को विशेष बल दिया गया है। यह शिक्षा नीति सरकारी स्कूलों में तो शुरू हो जाएगी लेकिन क्या महंगे प्राइवेट स्कूलों में भी लागू हो पायेगी। इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में जब स्कूल स्तर पर से ही यह मनोवैज्ञानिक व्यवस्था ऐसी बना दी जायेगी कि गरीब का बच्चा तो हेल्पर बनने की मानसिकता से पढ़ेगा और अमीर का बच्चा इंजीनियर डॉक्टर और वकील बनने के लिए पढ़ेगा तो तय है कि सरकारी स्कूलों की व्यवहारिक स्थिति इससे भी बत्तर होती जायेगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं बन चुकी है। इसलिए यहां बड़ा बाजार बनती जा रही है। यह बाजारीकरण ही सामाजिक असमानता का मूल बनता जा रहा है। शिक्षा में अटल आदर्श विद्यालय और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलकर राजनीतिक आकाओं के आगे तो स्थान बनाया जा सकता है लेकिन इससे समाज में बढ़ती गैर बराबरी को नहीं रोका जा सकेगा। आने वाले समाज में यह बाजारीकरण सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा यह तय है। विश्व बैंक की इन रिपोर्ट का व्यवहारिक संज्ञान लेकर इस वस्तु स्थिति के लिये जिम्मेदार तंत्र को जवाब देह बनाने के लिये अभी से कदम उठाने होंगे अन्यथा हर बार यह रिपोर्ट आती रहेगी और देश प्रदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का पात्र बनते रहेंगे।

शहरी योजनाओं पर निवेश में वर्ष 2014 के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि हुई:हरदीप सिंह पुरी

शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण वर्ष 2014 में 17 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 76 प्रतिशत हो गया है

शहरों से वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए नगरपालिका बांड जैसे नवीन तरीकों का उपयोग करने का आग्रह किया गया

शिमला। आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावास दिवस 2023 के अवसर पर कहा कि विश्व पर्यावास दिवस का महत्व अब तेजी से समझा जा रहा है। वर्ष 1980 के दशक में विश्व पर्यावास दिवस की अवधारणा का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावास दिवस की अवधारणा पहली बार वर्ष 1986 में केन्या के नैरोबी में प्रस्तुत की गई थी। विश्व पर्यावास दिवस के पहले उत्सव का विषय 'आश्रय मेरा अधिकार है' वर्ष 1986 की सबसे गंभीर समस्या-शहरों में पर्याप्त आश्रय की समस्या को रेखांकित करता है। मंत्री ने कहा कि तब से मानव बस्तियों के आस-पास चर्चा विकसित हुई है। अगले कुछ वर्षों में, वार्षिक विषय उस समय की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए- सुरक्षा से लेकर महिला सशक्तीकरण तक और स्वच्छता से लेकर काम की गरिमा तक अलग-अलग थीं।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से विकास के प्रति दृष्टिकोण भी विकसित हुआ है। सतत विकास लक्ष्य नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण से डिजाइन किए गए हैं और समावेशी और बॉटम-अप यानी नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

मंत्री ने भारत में शहरी स्थानों के विकास के बारे में बात करते हुए कहा कि शहरी परिवर्तन पर सरकार का ध्यान काफी बढ़ गया है। वर्ष 2014 से पहले शहरी विकास में उपेक्षा की जा रही थी। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच शहरी क्षेत्रों में केवल 1.78 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह परिवर्तन आया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, 'हमारे शहरों और कस्बों के परिवर्तन में वर्ष 2014 से 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है।'

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण की मात्रा लगभग 17 प्रतिशत थी और अब यह बढ़कर 76 प्रतिशत हो गयी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण 100 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि शहरी क्षेत्रों में विरासत में मिले कूड़े के ढेरों को भी अगले 2 वर्षों में बायोरेमेडिएशन के माध्यम से समाप्त कर दिया जाएगा।

पुरी ने कहा कि इस वर्ष का विषय 'लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएँ विकास और पुनर्प्राप्ति के संचालक के रूप में शहर' उपयुक्त रूप से चुना गया है। इस विषय पर चर्चा अब अधिक महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि दुनिया कोविड महामारी के व्यवधान के बिना अपने पहले वर्ष का आनंद ले रही है। उन्होंने कहा कि यह विषय महामारी के बाद की वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक सुधार और विकास के केंद्र के रूप में शहरों की भूमिका को रेखांकित करता है।

मंत्री ने शहरी स्थानों के सतत विकास के बारे में बात करते हुए कहा कि शहरी परिवहन और शहरी विकास से संबंधित अन्य नीतिगत विषयों में स्थिरता का तत्व शामिल है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे हरित विकल्पों का उल्लेख किया जिन्हें शहरी परिवहन में खालीपन को भरने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि को उसकी ऊर्जा खपत और उसके शहरी परिदृश्य से भी मापा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में शहरी क्षेत्र अर्थव्यवस्थाओं के उत्पादक केंद्र हैं, दुनिया की 75 प्रतिशत से अधिक सकल घरेलू उत्पाद यहीं से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा, 'भारत में, अपेक्षाकृत कम शहरीकरण के बावजूद, शहर पहले से ही राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 66 प्रतिशत का योगदान देते आ रहे हैं। 'वर्ष 2050 तक यह संख्या 80 प्रतिशत तक जाने की आशा है जब देश की आधी से अधिक आबादी इसके शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय शहरी अर्थव्यवस्थाओं को भविष्य में सुरक्षित बनाने पर केंद्रित है ताकि उन्हें ब्लैक स्वान ईवेंट यानी अप्रत्याशित घटनाओं, महामारी और ऐसी अन्य विनाशकारी घटनाओं से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके।

मंत्री ने शहरों से वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए नगरपालिका बांड जैसे नवीन तरीकों का उपयोग करने का आग्रह किया। संसाधन जुटाने के लिए नगरपालिका बांड का उपयोग करने के लिए शहरों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के माध्यम से, सरकार ने शहरों में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए बाजारों से धन प्राप्त करने के लिए दबाव डाला है। 12 शहरों ने नगरपालिका बांड के माध्यम से 4,384 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। इस तरह की कार्रवाइयों से स्थानीय शहरी निकायों की साख बढ़ी है और वे आकर्षक निवेश स्थल बन गए हैं।

मंत्री ने भारत के नियोजित शहरीकरण मॉडल के बारे में बात करते हुए कहा कि अंत्योदय से सर्वोदय पर ध्यान केंद्रित करने से यह सुनिश्चित हुआ है कि हमारे शहर अशांत समय में भी जीवंत और आर्थिक रूप से संपन्न बने रहें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम संचालित किए हैं और अपने शहरों में हरित परिवर्तन लाये हैं, उससे अन्य देश बहुत कुछ सीख सकते हैं।

विश्व पर्यावास दिवस

प्रत्येक वर्ष, विश्व पर्यावास दिवस अक्तूबर के पहले सोमवार को आयोजित किया जाता है और वैश्विक स्तर पर शहरी अक्तूबर की शुरुआत की जाती है। इस दिन वैश्विक स्तर पर एक समारोह का आयोजन किया जाता है, जो हर साल एक अलग देश में आयोजित किया जाता है, जिसमें मुख्य वक्ता और एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित गोलमेज चर्चाएँ होती हैं। विश्व पर्यावास दिवस पहली बार 1986 में केन्या के नैरोबी में 'आश्रय मेरा अधिकार है' विषय के साथ मनाया गया था।

इस वर्ष विश्व पर्यावास दिवस का वैश्विक अवलोकन 'लचीली शहरी अर्थव्यवस्था' के विषय के अंतर्गत किया गया। शहर विकास और पुनर्प्राप्ति के संचालक हैं। इस बात पर ध्यान दिया गया कि शहर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को निवासियों के लाभ के लिए किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं। विषय के अनुरूप, भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 9 अक्तूबर 2023 को विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक शोम्बी शार्प और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस आयोजन का फोकस विभिन्न शहरी हितधारकों को उन तरीकों पर चर्चा करने के लिए बुलाना था जिनसे शहरों को सतत विकास के लिए वर्ष 2030 के एजेंडे को प्राप्त करने के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्राथमिकता दी जा सके।

स्वेच्छा से स्वच्छता ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया

स्वच्छ भारत मिशन ने श्रमदान के लिए 9 लाख स्थानों पर 8.75 करोड़ लोगों को एकजुट किया

शिमला। 1 अक्तूबर को सुबह 10 बजे, स्वच्छ भारत की यात्रा का नया इतिहास लिखा गया। देश भर में एक विशाल स्वच्छता अभियान में स्वैच्छिक श्रमदान के लिए करोड़ों नागरिक आगे आये। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकप्रिय फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित बैयनपुरिया के साथ श्रमदान में शामिल हुए। उन्होंने ट्वीट किया, 'आज, जब देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अंकित बैयनपुरिया और मैंने भी वही किया! केवल स्वच्छता के अलावा, हमने इसमें फिटनेस और खुशहाली को भी शामिल कर लिया। यह स्वच्छ और स्वस्थ भारत की अनुभूति है!'

नागरिकों के स्वामित्व और नेतृत्व में, इस मेगा स्वच्छता अभियान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, गांवों और शहरों की भागीदारी देखी गई। कुल मिलाकर 9 लाख से अधिक स्थानों पर लगभग 8.75 करोड़ लोगों की भागीदारी का संकेत मिलता है। सड़कों, राजमार्गों और टोल प्लाजा, रेलवे ट्रैक और स्टेशनों, टोल प्लाजा, स्वास्थ्य संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, विरासत और पर्यटक स्थानों, आवासीय कॉलोनियों, जल निकायों, पूजा स्थलों, मलिन बस्तियों, बाजार क्षेत्रों, हवाई अड्डों और आसपास के क्षेत्रों, चिड़ियाघर और वन्यजीव क्षेत्र, गौशालाएं आदि में सफाई अभियान चलाया गया।

अनेक प्रथम पहलों वाले इस दिन, देश भर में इस जबरदस्त स्वच्छता अभियान को गति मिली, जिसमें स्वच्छता ने देश, पंचायतों, नगर पालिकाओं, जिलों और राज्य की सीमाओं से आगे बढ़कर एकजुट करने का कार्य किया। हजारों नागरिक समाज संगठनों और जनता के साथ अनेक राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व भी इसमें शामिल हुए। जवानों, नागरिकों, एनसीसी, एनएसएस और एनवाईके स्वयंसेवकों, एसएचजी, गैर सरकारी संगठनों,

आरडब्ल्यूए, बाजार संघों, उद्योग निकायों, धार्मिक नेताओं, मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों, यूट्यूबर्स, कलाकारों आदि ने इस जबरदस्त पहल के लिए मिलकर काम किया। सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संगठन ने 1000 सार्वजनिक शौचालयों को साफ करने के लिए लगभग 50,000 नागरिकों का नेतृत्व किया। माता अमृतानंदमयी के आश्रमों के नेटवर्क और अमृता संस्थानों के समूह ने निवासियों और भक्तों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सफाई की। ईशा फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने केंद्र के पास के ग्रामीण इलाकों में सड़कों, कॉलोनियों, शौचालयों की सफाई की। बाबा रामदेव योगपीठ ने 30,000 नागरिकों के साथ पार्कों, आवासीय क्षेत्रों और राजमार्गों सहित 1000 से अधिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस्कॉन के सैकड़ों स्वयंसेवक सड़कों की सफाई के लिए एकजुट हुए। क्रेडाई, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, ब्रिटानिया, बजाज, आदित्य बिड़ला, अमेज़ॅन आदि ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, इलैयाराजा जैसी हस्तियों, भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों और कई अन्य लोगों ने सार्वजनिक एकजुटता को प्रोत्साहित किया। रिकी केज, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, राजकुमार राव जैसे कई लोग जमीनी कार्यों में शामिल हुए। वक्फ बोर्ड, गुरुद्वारा स्वयंसेवक, रोटरी क्लब, आगा खां फाउंडेशन, रामकृष्ण मिशन जैसे संगठनों ने भी भागीदारी की। बीएमजीएफ, यूएसएआईडी, यूनिसेफ, जीआईजेड जैसे सेक्टर भागीदारों ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों के तहत विभिन्न संगठन अनूठी गतिविधियों के साथ आगे आये। केंद्रीय मंत्री भी विभिन्न स्थलों पर श्रमदान में शामिल हुए। 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के परिणामस्वरूप एक ही समय में लाखों स्थलों पर श्रमदान स्वयंसेवकों को सहज सुविधा उपलब्ध हुई। जब समर्पित स्वयंसेवकों के छोटे समूहों ने अपने चुने हुए स्थलों को साफ किया तो एक उपलब्धि की अनुभूति हुई। पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की अधिक थी। इस अविश्वसनीय समय में लोगों और नागरिक समाज संगठनों ने कचरा संग्रहण, कचरा उठाने, उसके सुरक्षित निपटान आदि के लिए पहल की। प्रत्येक श्रमदान स्थल पर शून्य अपशिष्ट और प्लास्टिक मुक्त का सिद्धांत अपनाकर आयोजन किया गया था।

24 सितंबर, 2023 को 105वीं मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के कार्य करने के आहवान के बाद, मिशन ने तेजी से एक सक्षम प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा तैयार किया, जहां लोग श्रमदान के लिए अपनी पसंदीदा साइट पर पंजीकरण, पहचान और चयन सकते थे। एक मजबूत बैकएंड बुनियादी ढांचा भी स्थापित किया गया, जिससे शहर के अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों, कॉर्पोरेट निकायों आदि को पंजीकरण करने की अनुमति मिली। कूड़ा-कचरे के प्रति संवेदनशील स्थलों की पहचान की गई और उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिससे जनता को अपनी पसंद की साइटों को चुनने और उनमें शामिल होने में मदद मिली। श्रमदान के दिन वे अपनी तस्वीरें भी अपलोड कर सकते हैं और भागीदारी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी सामाजिक व्यवहार परिवर्तन अभियान में आवश्यक होने के नाते, जनता को पहल के बारे में सूचित करने और उनकी भागीदारी के लिए अपील करने वाले सरल और समान संदेश गांवों और कस्बों में अपनाये गये। स्थानीय अंतर-व्यक्तिगत संचार, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और संचार के अन्य नवीन साधनों के मिश्रण का उपयोग करके पूरे देश में गति बनाई गई।

लोगों के इस सामूहिक प्रयास से निश्चित रूप से सभी स्थलों पर साफ-सफाई दिखाई देने लगी। स्वच्छ भारत मिशन के 9 वर्षों में, सामूहिक प्रयासों की ताकत को उजागर करते हुए लोग कई अवसरों पर एक साथ आए हैं। स्वच्छ राष्ट्र के लिए स्वैच्छिक प्रयास के लिए एक ही घंटे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ आना निश्चित रूप से दुनिया में अपनी तरह का अनोखा प्रयास है। जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के तहत यात्रा जारी है, इस तरह की सामूहिक कारवाई निश्चित रूप से वैज्ञानिक तरीके से कचरे के प्रबंधन और विरासत में मिले कचरे का उपचार 2026 तक कर कचरा मुक्त राष्ट्र के लिए कार्य करने की ताकत बढ़ाएगी।

एनएचपीसी जलविद्युत परियोजनाओं को जल्द से जल्द चालू करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है

शिमला। विद्युत मंत्रालय सिक्किम के तीस्ता बेसिन में अचानक आई बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। सचिव विद्युत पंकज अग्रवाल ने कल एनएचपीसी के साथ एक आपातकालीन बैठक की जिसमें विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

तीस्ता बेसिन में 3 और 4 अक्तूबर 2023 की मध्यरात्रि में अचानक आई बाढ़ के कारण तीस्ता V जलविद्युत स्टेशन से तारखोला/पम्फोक तक के सभी पुल डूब गए अथवा बह गए। इससे इन इलाकों में आवागमन और संचार गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। बाढ़ का पानी तीस्ता V जलविद्युत स्टेशन 510 मेगावाट के बांध के ऊपर तक पहुंच गया है। परियोजना स्थल के साथ-साथ आवासीय कालोनी के कुछ हिस्सों को जोड़ने वाली सभी सड़कें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फिलहाल पावर स्टेशन बंद है और बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। एनएचपीसी ने अपनी सभी परियोजनाओं से लोगों को समय पर हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की थी। मगर, तीस्ता V जलविद्युत स्टेशन से एक व्यक्तिके हताहत होने की सूचना है।

एनएचपीसी के निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना तीस्ता VI (500 मेगावॉट) का काम बाधित हो गया है। बाढ़ का पानी बिजली घर और ट्रांसफार्मर तक पहुंच चुका है। बैराज के साथ-साथ बिजली घर के दाएं और बाएं किनारों को जोड़ने वाले पुल भी बाढ़ की पानी में बह गए हैं। परियोजना स्थल पर काम कर रहे दो क्रेन ऑपरेटर लापता बताये जा रहे हैं। उनका पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है।

पश्चिम बंगाल के निचले इलाके में स्थित टीएलडीपी III (160 मेगावॉट) (तीस्ता लो डैम III जलविद्युत संयंत्र) और टीएलडीपी IV (132 मेगावॉट) विद्युत स्टेशनों में कोई बड़ी क्षति नहीं दिखी है। दोनों विद्युत स्टेशन सुरक्षित हैं लेकिन बाढ़ के पानी के साथ भारी गाद आने के कारण फिलहाल इन्हें बंद रखा गया है। इन दोनों परियोजनाओं से बिजली उत्पादन को जल्द से जल्द सुचारु करने के लिए एनएचपीसी लगातार कर रही है। इसके अलावा, रंगित घाटी में नुकसान की कोई सूचना नहीं है, जहां एनएचपीसी का रंगित IV विद्युत परियोजना (120 मेगावॉट) निर्माणाधीन है जबकि रंगित विद्युत स्टेशन (60 मेगावॉट) चालू है।

जल स्तर कम होने के बाद सभी परियोजना स्थलों पर हुए नुकसान का विस्तार से आकलन किया जाएगा। एनएचपीसी प्रभावित इलाकों में भोजन, दवा, बिजली आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन अधिकारियों और जिला प्रशासन की मदद से हर संभव प्रयास कर रही है।

भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एआईबीडी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया

शिमला। भारत एक अभूतपूर्व विकास के तौर पर 2018-2021 और 2021-2023 तक पहले ही एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एआईबीडी जनरल कान्फ्रेंस (जीसी) अध्यक्ष के रूप में दो कार्यकाल पूर्ण कर चुका है। भारत को इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व करने के लिए लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एआईबीडी जीसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 50 वर्ष पुराने संगठन एआईबीडी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और यह पूरे एशिया-प्रशांत और प्रसारण संगठनों के आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत पर विश्वास जता रही है कि भारत प्रसारण को एक नवीन आयाम प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करने के अलावा इस दिशा में नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

एआईबीडी, यूनेस्को के तत्वावधान में 1977 में स्थापित एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य संगठन हैं, जिनमें 26 सरकारी सदस्य देश शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 48 प्रसारण प्राधिकरण और प्रसारक एवं 44 सहयोगी संगठन करते हैं। इनमें एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राज्यों और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। भारत एआईबीडी के संस्थापक सदस्यों में से एक है और भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती एआईबीडी में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि निकाय है।

एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एआईबीडी के 21वें आम सम्मेलन और इससे संबंध बैठकें 2023 जीसी 2023 की अध्यक्षता एआईबीडी के अध्यक्ष और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने की और इसका समापन 02-04 अक्तूबर, 2023 को मारीशस के पोर्ट लुइस में सफलतापूर्वक हुआ। दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य नीति और संसाधन विकास के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत और सामंजस्यपूर्ण इलेक्ट्रानिक मीडिया वातावरण बनाना है।

एक अंतरराष्ट्रीय प्रसारण संस्थान में इस तरह के प्रतिष्ठित पद पर रहना न केवल भारत और प्रसार भारती के प्रति अंतरराष्ट्रीय मीडिया के मजबूत भरोसे को दर्शाता है, बल्कि प्रसारण के क्षेत्र में रणनीतिक रूप से भविष्य की उपलब्धियां हासिल करने हेतु भारत के लिए मजबूत आधारशिला भी रखता है।

73वें और 74वें संविधान संशोधन से बदली लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता:मुख्यमंत्री

एक लड़की वाले परिवार को दो लाख, दो लड़कियों के परिवार को एक लाख रुपए देने की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता बदल रही है, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे समाज में लड़कियों के प्रति धीरे-धीरे दृष्टिकोण बदला और आज हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में 56 प्रतिशत महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का बिल संसद द्वारा पास किया गया है, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया है।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम 1994 के तहत शिमला में दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआरएस डाटा 2018-20 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात 950 है, जो देश में तीसरे स्थान पर है तथा हमें पहले स्थान पर आने का लक्ष्य को हासिल करना होगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है।

मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार को मिलने वाले 35 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपए करने तथा दो बेटियों के बाद परिवार नियोजन पर मिलने वाले 25 हजार रुपए की राशि को एक लाख रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लड़कियां आज हर क्षेत्र में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। शिक्षा से लेकर सेना तथा अन्य क्षेत्रों में लड़कियां आगे निकल गई हैं। उन्होंने कहा कि वेदों और पुराणों में भी महिलाओं को अधिक सम्मान और महत्व दिया गया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों को घर-द्वार पर गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बड़े स्तर पर सुधार कर रही है। आधुनिक तकनीक को समाहित करके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों पर बोझ कम करने के लिए ब्लॉक स्तर के संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रयास के तहत 36 विधानसभा क्षेत्रों में 6-6 मेडिकल विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की है और जल्द ही 32 अन्य संस्थानों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक मशीनें भी लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए धन की कोई कमी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधार से लिंक कर हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि एक क्लिक पर व्यक्ति की पूरी मेडिकल हिस्ट्री पता लग सके।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिनियम के तहत सोनोग्राफी मशीन का पंजीकरण कराने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के उपयोग से प्रतिभागी अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी पंजीकरण करवा सकते हैं, जिससे उनके समय की बचत होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। साथ ही प्रत्येक आवेदन की वास्तविक समय स्थिति को ट्रैक करना भी संभव होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से एक सुरक्षित और प्रभावी डेटाबेस की सुविधा प्रदान करने में मददगार सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने भ्रूण हत्या रोकने के दृष्टिगत बेहतर काम करने के लिए जिला चंबा के भरमौर, जिला शिमला के ननखड़ी और मंडी जिला के जंजैहली ब्लॉक को सम्मानित किया, जिनमें लिंगानुपात क्रमशः 1015, 1087 और 996 है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने भ्रूण जांच करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आज समाज में लड़कियों के प्रति नज़रिया बदल रहा है। उन्होंने कहा कि लिंग जांच पर बनाए गए कानूनी प्रावधानों का हिमाचल प्रदेश में सख्ती से पालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में लिंगानुपात अच्छा है तथा इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए निरंतर जागरूकता अभियान भी राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से बालिका प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार अनेक योजनाएं चला रही हैं।

इस अवसर पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, विशेष सचिव स्वास्थ्य नीरज कुमार, विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।

एचपीएसईडीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 8.16 करोड़ रुपये लाभ अर्जित किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के निदेशक मंडल की 106वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को नवीनतम सूचना

प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रीन फील्ड और उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने से सुशासन के साथ-साथ पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि एचपीएसईडीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 8.16 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया है तथा वित्त वर्ष 2022-23 में निगम का कुल कारोबार (राजस्व) 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। उन्होंने कहा कि निगम के इतिहास में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो कि इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि और सफलता का संकेत देती है।

मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि निगम की कार्य प्रणाली को पूरी तरह से स्वचालित कर दिया गया है और विभाग और विक्रेताओं से संबंधित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। निगम ने पहली बार सरकार को लाभांश भी प्रदान किया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पांच रुपये प्रति शेयर की दर से कुल 18 लाख 58 हजार 350 रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रति शेयर 20 रुपये उच्च लाभांश के साथ कुल 74 लाख 33 हजार 400 रुपये के चेक मुख्यमंत्री को भेंट किए।

आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने तथा सरकार के राहत एवं पुनर्वास कार्य में योगदान देने के उद्देश्य से निदेशक मण्डल ने आपदा राहत कोष के लिए 21 लाख रुपये का चेक भी भेंट किया।

एचपीएसआईडीसी के प्रबन्ध निदेशक मुकेश रेपसवाल ने कार्यवाही का संचालन किया।

बैठक में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, सचिव डिजिटल टेक्नॉलाजी एवं गवर्नेंस डॉ. अभिषेक जैन, निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति, बीएसएनएल के सीजीएम जसविंदर सिंह सहोता और मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा उपस्थित थे।

डा.विवेक बिंदल को हिमाचल गौरव अवार्ड

शिमला/शैल। हिमाचल के सबसे बड़े गैर सरकारी मेले हिमाचल उत्सव के 19वें संस्करण में जानेमाने रोबोटिक सर्जन डा. विवेक बिंदल को हिमाचल गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोलन के निवासी और पूर्व मंत्री राजीव बिंदल के बेटे डॉ. विवेक बिंदल हिंदुस्तान के अग्रणी रोबोटिक विशेषज्ञों में शुमार हैं। साल

2003 में हिमाचल पीएमटी में टाप करने के बाद विवेक बिंदल ने मौलाना अबुल कलाम आजाद मेडिकल कालेज से अपनी पढ़ाई करने के बाद सर गंगाराम अस्पताल और उसके बाद अमेरिका जाकर रोबोटिक सर्जरी में सुपर स्पेशलाइजेशन हासिल की। वर्तमान में दिल्ली के मैक्स हेल्थकेयर में रोबोटिक सर्जरी के विभाग में डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर कार्यरत हैं। वर्तमान में डॉ. बिंदल देश की कई नेशनल और इंटरनेशनल प्रोफेशनल सोसायटीस में लीडरशीप पोजिशन पर हैं और अब तक उनके 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रतिष्ठित इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। कई प्रथम अपने खाते में दर्ज करने वाले डॉ. विवेक बिंदल को सबसे कम उम्र के बच्चे की बैरियेटिक सर्जरी करने का श्रेय प्राप्त है। उनके द्वारा आईजीएमसी में की गई बैरियेटिक सर्जरी को आडिटोरियम में बैठे 200 से ज्यादा विशेषज्ञों ने लाईव देखा। डायनामिक इंडिया युवा मंडल द्वारा हिमाचल गौरव सम्मान देने के समय हजारों दर्शकों ने तालियां बजाकर डॉ. बिंदल का जोरदार अभिवादन किया।

दुबई की कम्पनी ने दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से चिकित्सा आपूर्ति की पेशकश की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से यूनाइटेड पार्सल सर्विस कम्पनी की वाइस प्रेजिडेंट क्रिस्टिना स्टूलर द कोस्टा और निदेशक दिनकर सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कम्पनी यूनाइटेड पार्सल सर्विस ने हिमाचल प्रदेश के राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने की पेशकश की है। दुबई स्थित कम्पनी ने राज्य सरकार को प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में दवाएं और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करने की पेशकश की है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने सरकार को आवश्यक दवाओं और टीकों की निःशुल्क आपूर्ति का भी आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण के दृष्टिगत कम्पनी के इस प्रस्ताव पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी टेकनालॉजी एवं गवर्नेंस

विभाग इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा और राज्य सरकार उसी के अनुरूप सेवाओं के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के अमूल्य सहयोग से आपदा राहत कोष में 200 करोड़ रुपये से अधिक का अंशदान किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए समाज के हर वर्ग द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। यह सहयोग प्रदेश के राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहायक सिद्ध हो रहा है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी एंड गवर्नेंस सचिव डा. अभिषेक जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने शोघी में विज्ञान अध्ययन एवं सृजन केन्द्र का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के शोघी में 11 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विज्ञान अध्ययन एवं सृजन केन्द्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित विज्ञान अध्ययन एवं सृजन केन्द्र विज्ञान शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाने के साथ-साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा। यह अत्याधुनिक संस्थान हिमकोस्टे और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद एनसीएसएम के संयुक्त तत्वावधान में तैयार किया गया है। इसके सभी संस्थागत खण्डों में 60 इंटरैक्टिव विज्ञान प्रदर्शनियां, विषयवार दीर्घाएं और सूचना विज्ञान प्रदर्शनियां हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र में एक आधुनिक तारामंडल का संचालन वर्ष 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा जो खगोलीय शिक्षा को प्रोत्साहित करने में मददगार साहिब होगा। उन्होंने केंद्र में प्रदर्शित प्रदर्शनियों का गहराई से अवलोकन करते हुए कहा कि यह केन्द्र प्रदेश में नवीन विचारों और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में आधारशिला रखने के साथ शुरू हुई इस परियोजना को वर्ष 2023 को मूर्तरूप मिला है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्रांति के जनक हैं और आज उनके प्रयासों के फलस्वरूप देश सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

उन्होंने कहा कि इस केंद्र की स्थापना से युवा मन में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वे वैज्ञानिक सिद्धांतों को अधिक प्रभावी ढंग से

समझ सकेंगे। इसके अलावा, प्रदेश के विद्यार्थियों को विज्ञान के अध्ययन व अनुभव के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि देश के अग्रणी वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए इस केंद्र में एक हाल ऑफ फेम स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसने एक पुस्तकालय और एक यू-ट्यूब स्टूडियो भी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुविधा के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया गया है, जिससे प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को विज्ञान से संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित होने में सुविधा होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट भी जारी की।

मुख्यमंत्री ने विज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इस केंद्र को खोलने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह केंद्र युवाओं की वैज्ञानिक प्रतिभा को पोषित करने और विज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक एवं अनुभव आधारित शिक्षा भी जरूरी है।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के आधुनिक भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के परिकल्पना को साकार करता है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बनेगा।

पुनर्निर्माण कार्यों में लाएं तेजी:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी जिले में बरसात के दौरान बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों और भवनों के पुनर्निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के मकसद से 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे सभी प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी। उन्होंने यह बात मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों का दौरा करते हुए कही।

सांसद प्रतिभा सिंह ने इस दौरान बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों भौण, धनेसरी, शिव मंदिर देरडु, जड़ोल और जाम्बला में नुकसान का जायजा लिया तथा लोगों की समस्याओं को सुना।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश को इस आपदा से निपटने में कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने स्वयं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर हिमाचल प्रदेश को विशेष मदद की मांग की थी, जो आज दिन तक पूरी नही हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा के नेता भी इस आपदा की इस घड़ी में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

सांसद ने कहा कि समूचे राज्य के साथ मंडी संसदीय क्षेत्र में भी इस बरसात में बहुत अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिन-रात राहत व पुनर्वास कार्यों में जुटी है ताकि शीघ्रातिशीघ्र प्रभावित लोगों के जीवन को पटरी पर लाया जा सके।

इससे पूर्व, सांसद ने 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित राजकीय प्राथमिक पाठशाला भौण के अतिरिक्त भवन व स्मार्ट क्लासरूम का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत के पास ही में शिव मंदिर देरडु के सराय भवन और जांबला ग्राम पंचायत में पंचायत घर की प्रथम मजिल का उद्घाटन भी किया।

इस अवसर पर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ने कहा की प्रदेश सरकार आपदा की मुश्किल घड़ी में हर समय जनता के साथ खड़ी है। उनकी हर संभव मदद की जा रही है।

इस दौरान पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

डेढ़ वर्ष में पूर्ण करें दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र डगवार का निर्माण कार्यः मुख्यमंत्री

संयंत्र निर्माण पर प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपये होंगे व्यय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बोर्ड के सहयोग से जिला कांगड़ा के डगवार में 1.5 लाख

लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास शीघ्र ही किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपये के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोजेरेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके लिए चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना जिला के दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीद कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।

उन्होंने दूध खरीद में पारदर्शिता के महत्त्व पर बल देते हुए कहा कि इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूध खरीद प्रणाली को मजबूत करने के लिए 43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। संयंत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन 2.74 लाख लीटर दूध खरीदने का लक्ष्य रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के तहत डगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में मिल्क पाउडर, आइसक्रीम और विभिन्न प्रकार के पनीर का उत्पादन शुरू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस प्लांट के निर्माण संबंधी कार्य को डेढ़ वर्ष के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र में उल्लेखित वायदे के अनुसार गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदने के लिए प्रतिबध है। उन्होंने कहा कि राज्य के कृषि और आर्थिक विकास के लिए यह पहल महत्त्वपूर्ण है और प्रदेश सरकार राज्य में डेयरी-आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबधता से कार्य कर रही है।

एनडीडीबी के अध्यक्ष डा. मीनेश शाह ने परियोजना पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और इस संयंत्र की स्थापना में हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

स्वास्थ्य मंत्री डा. कर्नल धनी राम शाडिल, कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक विनय कुमार और इंद्र दत्त लखनपाल, प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सचिव राकेश कंवर, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल-2023 का टीजर जारी किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल-2023 का टीजर जारी किया। यह फेस्टिवल 12 से 15 अक्तूबर,

2023 तक हिमाचल पर्यटन विभाग और दि-ग्लाइड इन के संयुक्त तत्वावधान में शिमला के समीप जुन्गा में आयोजित किया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष वर्ष मानसून के दौरान लगभग तीन माह तक प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं के कारण भारी क्षति हुई है। प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय पर भी इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया। प्रदेश में अब जनजीवन सामान्य है और आवागमन के लिए सभी सड़कें खोल दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन गतिविधियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।

उन्होंने कहा कि शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के आयोजन से साहसिक गतिविधियों के साथ-साथ पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में साहसिक पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में सभी पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर एस बाली, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क राजीव कुमार, ग्लाइड इन के प्रबन्ध निदेशक अरुण रावत और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

डीपीआर 490 करोड़ की और निविदा आयी 920 करोड़ की

शिमला/शैल। शिमला के लिये 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जब नगर निगम शिमला के महापौर और उपमहापौर दोनों पदों पर माकपा का कब्जा था तब विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना पर विचार किया गया था। उस समय के प्रयासों के चलते 2022 में इस परियोजना की डीपीआर 2022 में फाइनल हुई। डीपीआर में परियोजना की लागत 490 करोड़ आंकी गयी थी। इस आकलन के बाद अक्तूबर 2022 में इसके लिए निविदयें आमंत्रित की गयी और 790 करोड़ की निविदा उसी कम्पनी की आ गयी जिसने पहले निविदा दी थी। 790 करोड़ की निविदा आने पर सवाल उठे। क्योंकि सी पी एच ई ई ओ ने 2022 में ही 490 करोड़ की डीपीआर अनुमोदित की थी। ऐसे में अक्तूबर 2022 में यह रेट बढ़ाकर 790 करोड़ हो जाये तो किसी का भी माथा आवश्यक ठनकेगा ही। इस पर एसजेपीएनएल ने उस समय यह निविदा रद्द कर दी। इसके बाद मार्च 2023 में पुनः निविदायें आमंत्रित की गयी। इस बार भी उन्हीं लोगों ने निविदायें डाली जिन्होंने पहले डाली थी। लेकिन इस बार यह निविदा 920 करोड़ की आयी है।

ऐसे में यह सवाल उठाना स्वभाविक है कि जो डीपीआर 490 करोड़ की आंकलित हुई हो उसकी निविदा एक वर्ष से भी कम समय में ही मूल के दो गुना से भी कैसे बढ़ जाये? क्या डीपीआर बनाने वाले लोग सक्षम नहीं थे? क्या विश्व बैंक के अधिकारियों ने भी इस पर आंख बंद कर ली थी? यह परियोजना कर्ज के पैसे से शक्ल लेगी और इस कर्ज की अदायगी प्रदेश की जनता करेगी। ऐसे में निविदा दरों में इतनी भिन्नता आना कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि इसके लिये निविदायें डालने वाले पिछले दो-तीन बार से वही दो लोग हैं। क्या ऐसे में यह आशंका नहीं उभरती की कहीं यह दोनों लोग आपस में मिलकर ही यह खेल तो नहीं खेल रहे हैं। क्या एक वर्ष से कम समय में इसकी दरों में 131% की बढ़ौतरी कैसे हो गयी? जब इस पर 2022 से ही सवाल उठाये जा रहे हैं और पत्र लिखे जा रहे हैं तो उनका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। मुख्य सचिव को भी इस बारे में पत्र लिखा गया है लेकिन उस पर कोई कारवाई होना अब तक सामने नहीं आया है।

शिमला जल प्रबंधन निगम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
पूर्व उपमहापौर टिकेन्द्र पंवर ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

इसी के साथ यह सवाल भी उठ रहा है की शिमला के लिए 500 करोड़ की स्मार्ट सिटी परियोजना परिकार्यन्वित की गयी थी जो उसके लिये चिन्हित की गयी। 210 परियोजनाओं में शिमला के लिये जलापूर्ति की कोई योजना क्यों नहीं रखी गयी? क्या उसमें शिमला को लोहे का जंगल बनाने से अधिक कुछ नहीं सोचा गया। अब तक स्मार्ट सिटी के नाम पर 868.26 करोड रुपए खर्च किये जा चुके हैं। इसमें कुछ एक कार्यो की व्यवहारिकता पर सवाल भी उठने शुरू हो गये हैं। संजौली से आईजीएमसी तक 23.33 करोड से बने कवर्ड फुटपाथ का औचित्य सवालों में है। इसी तरह 13.50 करोड़ की लागत से बन रही लिफ्ट पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह लिफ्ट इसमें काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन निकाल पायेगी। इसी तरह छोटा शिमला से आयुर्वेद अस्पताल तक 12.78 करोड़ की लागत से बन रहे रास्ते के औचित्य पर सवाल उठ रहे हैं। जल परियोजनाओं पर उठते सवालों से स्मार्ट सिटी योजनाओं के कार्य भी चर्चा में आ गये हैं। देखना रोचक होगा कि सरकार इस पर जांच करवाती है या नहीं।

पेपर लीक मामले की जांच में लंबा समय लगने की संभावना

- अभी मामला एसएफएसएल के पास लंबित है
- एसएफएसएल में रिपोर्टिंग का पद रहा है खाली
- 10000 अभ्यार्थियों का भविष्य जांच पूरी होने तक लटका

शिमला/शैल। सुक्खु सरकार ने अधीनस्थ सेवाचयन बोर्ड को पेपर लीक होने की शिकायते आने के बाद बोर्ड के संबंद्ध अधिकारियों/ कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद विस्तृत जांच के लिये एक एस.आई.टी. का गठन कर दिया था। एस.आई.टी की जांच जैसे ही आगे बढ़े तो कई और परीक्षाओं में भी पेपर लीक होने के मामले सामने आये। करीब एक दर्जन मामले इस बोर्ड के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। इतने सारे मामले बन जाने के बाद सरकार ने इस बोर्ड को ही भंग कर दिया और इसका काम भी लोक सेवा आयोग को दे दिया। यह मामले बनने के बाद हजारों अभ्यार्थियों का भविष्य लटक गया। क्योंकि जिन परीक्षाओं में पेपर लीक होने के आरोप लगे थे उनके परिणाम घोषित होने से लटक गये। इस पर अभ्यार्थियों में रोष पनपना शुरू हो गया। अभ्यार्थी आन्दोलन करने के लिये विवश हो गये। मुख्यमंत्री से मिलने पर भी आश्वासनों से अधिक कुछ नहीं मिल पाया। विधानसभा तक भी यह प्रकरण पहुंच गया। सरकार ने जल्द ही नई व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद अब एक नये राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना के साथ ही अधिकारियों की भी तैनाती कर दी गयी है। लेकिन इस अधिसूचना के जारी होने से भी उन अभ्यार्थियों का मसला तो हल नहीं हो सकता जिनके परिणाम मामले बनने से लटके हुये हैं। क्योंकि जिन परीक्षाओं को लेकर मामले बन चुके हैं उनके परिणाम तो जांच पूरी होने के बाद ही घोषित हो पायेंगे। जांच पूरी होने के बाद चालान अदालत में जायेंगे और फिर अदालत का फैसला आने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी। इस तरह लम्बे समय तक इन अभ्यार्थियों को इन्तजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो मामला फॉरेंसिक परीक्षण के लिए एसएफएसएल जुन्गा के डॉक्यूमेंट फोटोग्राफी विभाग में लंबित पड़ा है। क्योंकि वहां पर जांच के लिये कोई रिपोर्टिंग अधिकारी ही तैनात नहीं है। जबकि सरकार यह जांच तेजी से चल रही होने का दावा कर रही है। विजिलैन्स जांच में जिन परीक्षाओं के परिणाम फंसे हुये हैं उनमें करीब 10000 अभ्यार्थी और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। 3 अक्तूबर 2023 को आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी के जब तक रिपोर्टिंग अधिकारी की तनाती नहीं हो जाती तब तक यह मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अभी तक रिपोर्टिंग अधिकारी की तैनाती न किये जाने से यह आशंका बढ़ती जा रही है की क्या यह सरकार जानबूझकर इस मामले को लम्बा बढ़ाना चाहती है। आरटीआई की इस जानकारी से अभ्यार्थीयों और उनके अभिभावकों में रोष बढ़ने की संभावना है।

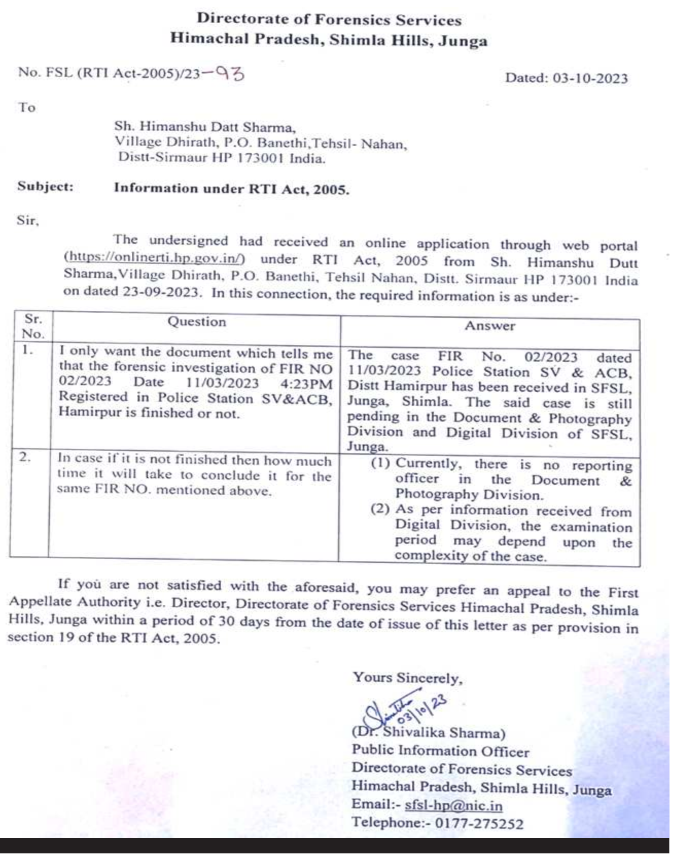
Directorate of Forensics Services
Himachal Pradesh, Shimla Hills, Junga

No. FSL (RTI Act-2005)/23-93 Dated: 03-10-2023

To

Sh. Himanshu Datt Sharma,
Village Dhirath, P.O. Banethi,Tehsil- Nahan,
Distt-Sirmaur HP 173001 India.

Subject: Information under RTI Act, 2005.

Sir,

The undersigned had received an online application through web portal (https://onlinerti.hp.gov.in/) under RTI Act, 2005 from Sh. Himanshu Dutt Sharma,Village Dhirath, P.O. Banethi, Tehsil Nahan, Distt. Sirmaur HP 173001 India on dated 23-09-2023. In this connection, the required information is as under:-

Sr. No.	Question	Answer
1.	I only want the document which tells me that the forensic investigation of FIR NO 02/2023 Date 11/03/2023 4:23PM Registered in Police Station SV&ACB, Hamirpur is finished or not.	The case FIR No. 02/2023 dated 11/03/2023 Police Station SV & ACB, Distt Hamirpur has been received in SFSL, Junga, Shimla. The said case is still pending in the Document & Photography Division and Digital Division of SFSL, Junga.
2.	In case if it is not finished then how much time it will take to conclude it for the same FIR NO. mentioned above.	(1) Currently, there is no reporting officer in the Document & Photography Division. (2) As per information received from Digital Division, the examination period may depend upon the complexity of the case.

If you are not satisfied with the aforesaid, you may prefer an appeal to the First Appellate Authority i.e. Director, Directorate of Forensics Services Himachal Pradesh, Shimla Hills, Junga within a period of 30 days from the date of issue of this letter as per provision in section 19 of the RTI Act, 2005.

Yours Sincerely,
03/10/23
(Dr. Shivalika Sharma)
Public Information Officer
Directorate of Forensics Services
Himachal Pradesh, Shimla Hills, Junga
Email:- sfsl-hp@nic.in
Telephone:- 0177-275252